Recommendations of expert group on delineation of New Hill Areas

*136. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to UQ. 1775 given in the Rajya Sabha on 27-3-1990 and state:

(a) what are the main recommendations of the Export Group on Delineation of New Hill Areas; and

(b) whether the development schemes in regard to Eastern Ghats are being considered by the Planning Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) Sir, the main recommendations of the Expert Group relate to evolving of criteria and listing of such areas of the country that conform to the crtieria evolved.

(b) No, Sir.

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी की मांगें

*137. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के संबंध में जनवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह के दौरान सरकार से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के समक्ष क्या मांगें रखी थीं ;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गई हैं और यदि शेष किसी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने सरकार को दिए गए अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित मांगें रखी थीं :

1. अखबारी कागज :

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को अपनी आबंटन सीमा के अंतर्गत अपनी इच्छानुसार किसी भी मिल से अपेक्षित स्वदेशी अखबारी कागज उठाने की छूट होनी चाहिए ।

मिलों को मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके तहत स्वदेशी अखबारी कागज की कीमत आयातित अखबारी कागज के जहाज उतरते मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए छोटे और मझौले समाचारपत्रों को दी जाने वाली सहायता जारी रखी जानी चाहिए । अखबारी कागज के आयात का विसंरीकरण किया जाना चाहिए । सरकार को 1990-91 के लिए शेष 60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को रुपया भुगतान क्षेत्र (आर0पी0ए0) से सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी0सी0ए0) में तबदील करने पर विचार करना चाहिए ।

2. सीमा शुल्क :

अखबारी कागज पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिए और समाचार पत्र उद्योग को कच्चे माल, उपभोज्य वस्तुओं, अतिरिक्त पुर्जों, हिस्सों, उपकरणों, मशीनरी इत्यादि पर सहायक सीमा शुल्क में वृद्धि से छूट दी जानी चाहिए । समाचारपत्र उद्योग को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई नबंबर, 1990 की अधिसूचना के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दी जानी चाहिए जिसके तहत वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कच्चे माल, घटकों, उपभोज्य वस्तुओं इत्यादि और अतिरिक्त कल पुर्जों के आयात को निलंबित किया गया है ।

3. सरकारी विज्ञापनों के लिए विज्ञापन दर :

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की दर न्यूनतम वाणिज्यिक दर पर नियत की जानी चाहिए ।

4. औद्योगिक संबंध :

(1) प्रेस की आजादी को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें पत्रकार और प्रेस प्रभावकारी रूप से और निर्भीक होकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें ।

समाचारपत्र कर्मचारी विशेषज्ञ समिति भंग कर देनी चाहिए ।

(2) सरकार ने उपयुक्त मांगों का अध्ययन करने के लिए सचिवों के एक दल का गठन किया है । सरकार ने सचिवों के दल की रिपोर्ट पर विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :--

एक. इस शर्त को, कि समाचारपत्र प्रतिष्ठान देशी कोटा उठाने के बाद ही आयातित अखबारी कागज का कोटा उठा सकते है, जारी रखा जाए । लेकिन इस बात पर जोर देना जरुरी नहीं होगा कि प्रत्येक समाचारपत्र को किसी विशिष्ट मिल से ही अपना कोटा उठाना होगा ।

दो. अखबारी कागज के प्रत्येक संशोधन के बाद, उद्योग मंत्रालय को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या मिलों द्वारा घोषित कीमतों में वृद्धि औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं ।

तीन. आयातित अखबारी कागज के विसरणीकरण (डिकेंटेलाइजेशन) के अनुरोध के संबंध में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

चार. सूचना और प्रसारण मंत्रालय को विज्ञापनों पर एक नए दर ढांचा दल (रेट स्ट्रक्चर ग्रुप) का गठन करना चाहिए ।

पांच. गृह मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करे कि पत्रकारों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए ।

(3) सचिवों के दल ने पाया कि इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी की अखबारी कागज पर सीमा शुल्क समाप्त करने की मांग पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है । दल का यह भी विचार था कि कच्चे माल, कलपुर्जों, उपभोज्य सामग्री आदि पर सहायक सीमा शुल्क में वृद्धि पर छूट देने संबंधी उनकी मांग भी औचित्यपूर्ण नहीं है ।

(4) चूंकि ईश्वरी प्रसाद समिति की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय ने प्राप्त की थी और इसकी सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा रहा था, इसलिए इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी का, समिति को समाप्त करने का अनुरोध निष्फल पाया गया ।

C and AG's report on the Central Investment subsidy scheme

*138. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report of the Comptroller and Auditor General (CAG) on the implementation of the Central investment subsidy scheme and the growth centres scheme;

(b) if so, what are the findings and recommendations made; and

(c) what remedial measures are proposed to be taken?